Government and the House to the procedure of releasing funds from the Prime Minister's National Relief Fund, which is highly beneficial for the poor and needy patients, but there something needs to be done for its betterment. I appreciate the prompt sanction of financial assistance by the Prime Minister's Office on the recommendation of the Members of Parliament. Besides financial assistance, the Scheme gives the poor patients some kind of mental relief and a sense of confidence.

But recently there are instances where the requests of patients have been rejected on account of the fact that the initial requests were received after the surgery. I may point out that in order to save the lives of patients, in emergency cases, the doctors are forced to conduct surgery. So, it is not reasonable to reject the requests of the patients on this ground. Similarly, the financial assistance which is already sanctioned to the patients, is not given to their legal heirs. Generally, the expenses towards treatment and surgery of poor patients are met by their relatives by selling their belongings and by taking loans. The relevant rules, therefore, need to be amended to enable the patient or his legal heirs -- in the event of death of the patient -- to receive the financial assistance. The amounts sanctioned nowadays are not enough to meet the expenses of treatment. So, there is a genuine need for increasing the amount.

I earnestly request the hon. Prime Minister to take appropriate steps on the above matters so as to enhance the utility of the scheme.

Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 2-10 p.m.

The House then adjourned for lunch at ten minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fourteen minutes past two of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE INDIAN UNIVERSITIES (REPEAL) BILL, 2000

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Madam Deputy Chairman, on behalf of Dr. Murli Manohar Joshi, I move for leave to introduce a Bill to repeal the Indian Universities Act, 1904.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI O. RAJAGOPAL: Madam, I introduce the Bill.

उपसभापति : ये मक्खी कहां से आ गई ?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : अगर मच्छर आ सकते हैं तो मक्खी भी आ सकती है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: *Makhi*, you have come without being duly elected! Even *macchar* cannot come!

THE WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 2000

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

" कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

महोदया, जैसा कि माननीय सदस्यगण जानते ही हैं कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत काम के दौरान चोट लगने तथा जिन कतिपय व्यावसायिक बीमारियों के कारण अपंगता अथवा मृत्यु हो जाती है, उनके मामले में कामगारों और उनके परिवारों को मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है । इस समय यह अधिनियम रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों और अधिनियम की अनुसूची-2 में उल्लिखित जोखिमपूर्ण रोजगारों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। अनुसूची-2 में कारखानों, खानों, बागानों, निर्माण कार्य आदि में नियोजित व्यक्ति शामिल हैं ।

महोदया, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्र में क्रमिक विस्तार से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुप्रयोग का क्षेत्र कुछ हद तक कम हुआ है, तथापि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का क्षेत्र कारखानों और अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित कुछ अन्य प्रतिष्ठानों तक ही सीमित है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम बाकी क्षेत्रों में लागू है ।

महोदया, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में पिछली बार 1995 में संशोधन किया गया था। वर्ष 1994 में श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मुआवजा लाभों को और उदार बनाने के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं । संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की अब राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के परामर्श से जांच कर ली गई है । समिति की सिफारिशों और इस संबंध में प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है :-

I. अधिनियम की धारा 2(I)(ढ) में संशोधन किया जा रहा है ताकि बिना किसी अपवाद के सभी नैमित्तिक कर्मकारों को इसमें शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके ।